गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 327
दि. 31.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

जनगणना 2027 की तैयारी तेज, 33 सवालों के साथ शुरु होगी देश की सबसे बड़ी डेटा प्रक्रिया

नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण और व्यापक असर डालने वाली खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 33 अहम सवाल जारी कर दिए हैं। यह कदम न केवल देश की जनसंख्या से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे नीति निर्माण, विकास योजनाओं और संसाधनों के बेहतर वितरण का रास्ता भी साफ होगा। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास और आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रही है, जिसमें पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है।

जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो सितंबर 2026 तक चलेगा। इस चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जिसमें देशभर के हर घर, उसकी संरचना और उपयोग से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें नागरिकों की विस्तृत गणना की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने 11,718 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जो इसकी व्यापकता और महत्व को दर्शाता है।

इस बार जनगणना में तकनीक का विशेष उपयोग किया जा रहा है। देश के हर भवन को एक यूनिक आईडी देने के साथ-साथ उसकी जियो-टैगिंग की जाएगी, जिससे हर घर की सटीक लोकेशन और पहचान सुनिश्चित हो सके। यह कदम भविष्य में शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में बेहद सहायक साबित होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बन सके।

सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक FAQ पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां जनगणना से जुड़े सवालों के जवाब सरल भाषा में उपलब्ध होंगे। यह पहल

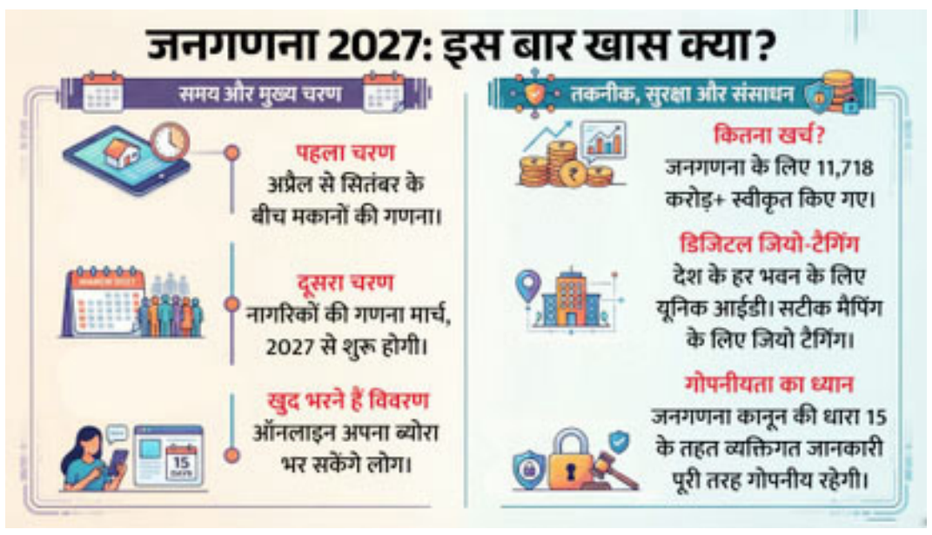

खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी, जो इस प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की शंका या भ्रम में हैं। इसके माध्यम से लोग न केवल जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि अपनी भागीदारी को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

इस जनगणना का एक महत्वपूर्ण और चर्चित पहलू यह है कि इसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई जोड़ा अपने संबंध को स्थिर और दीर्घकालिक मानता है, तो उसे विवाहित के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह बदलाव समाज में बदलती जीवनशैली और रिश्तों की नई परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो इस जनगणना को अधिक समावेशी और यथार्थवादी बनाता है।

जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की शुरुआत मकान से जुड़ी बुनियादी जानकारी से होगी, जैसे बिल्डिंग नंबर, जनगणना हाउस नंबर, और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री—फर्श, दीवार और छत का प्रकार। इसके बाद घर के उपयोग, उसकी स्थिति और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी ली जाएगी। अंत में परिवार के मुखिया से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसमें उनका नाम, लिंग, सामाजिक वर्ग और घर के स्वामित्व की स्थिति शामिल होगी। ये सभी आंकड़े मिलकर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करेंगे।

जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता को लेकर भी स्पष्ट आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत नागरिकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसे न तो आरटीआई के तहत साझा किया जा सकता है, न ही किसी अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और न ही किसी अन्य संस्था के साथ साझा किया जाएगा। यह प्रावधान नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वे बिना किसी भय या संकोच के अपनी जानकारी साझा कर सकें।

इस पूरी प्रक्रिया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उनकी प्रशासनिक मशीनरी जमीनी स्तर पर काम करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि हर घर और हर व्यक्ति तक यह प्रक्रिया सही तरीके से पहुंचे। गणकों की टीम घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से छूट न जाए।

जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की नींव है। इसके आधार पर ही सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है, बजट का वितरण करती है और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और सही जानकारी प्रदान करे।

आधुनिक तकनीक, व्यापक दायरा और सामाजिक बदलावों को समाहित करने वाले इस नए स्वरूप के साथ जनगणना 2027 न केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया होगी, बल्कि यह भारत के वर्तमान और भविष्य का एक विस्तृत दस्तावेज भी बनेगी। यह प्रक्रिया देश की विविधता, उसकी चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का सबसे सशक्त माध्यम है, जो आने वाले वर्षों में भारत की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, इजरायल के हमलों से ईरान और लेबनान में हालात गंभीर

यरुशलम/बेरूत। मध्य पूर्व में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, जहां Israel ने Iran और Lebanon में एक साथ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को भी इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों, प्रमुख बुनियादी ढांचों और तेहरान स्थित एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए लगातार हवाई हमले किए। इन हमलों के दौरान राजधानी तेहरान में रातभर धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे पूरे शहर में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बना रहा।

इजरायली सेना का दावा है कि उसने तेहरान में ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल आधुनिक हथियारों के विकास और सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इसी क्रम में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर स्थित एक रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया गया, जिसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ा माना जाता है। हालांकि ईरान की ओर से इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है, लेकिन इस हमले ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि संघर्ष अब केवल सीमित सैन्य

ठिकानों तक नहीं, बल्कि रणनीतिक और संस्थागत ढांचे तक पहुंच चुका है।

इसी बीच ईरान के उत्तरी शहर तबरीज में स्थित एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर भी इजरायल ने हवाई हमला किया। सरकारी मीडिया के अनुसार इस हमले में संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा और आग लग गई, जिसे बाद में दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। यह हमला न केवल औद्योगिक ढांचे पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है, बल्कि इससे क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

दूसरी ओर, लेबनान में भी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले तेज कर दिए हैं, जहां उसका सामना Hezbollah से हो रहा है। लेबनान की सेना के मुताबिक, टायर शहर के पास स्थित एक सैन्य चौकी पर इजरायली हमले में एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस महीने की शुरुआत में संघर्ष तेज होने के बाद से अब तक लेबनान की सेना के कई जवान मारे जा चुके हैं, जो इस युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है।

उधर, दक्षिणी लेबनान में जारी झड़पों के दौरान इजरायल का भी एक सैनिक मारा गया है। सेना ने उसकी पहचान 19 वर्षीय सार्जेंट लिरान बेन जियोन के रूप में की है। मार्च की शुरुआत से अब तक इजरायल के कई सैनिक इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे यह साफ है कि यह लड़ाई अब दोनों पक्षों के लिए भारी पड़ रही है।

बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भी इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। सोमवार को एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें Hezbollah के तीन सदस्यों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। जिस इमारत को निशाना बनाया गया, वह घनी आबादी वाले इलाके में स्थित थी, जिससे आम नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल और गहरा हो गया है। हमले के बाद हिज्बुल्लाह के सशस्त्र सदस्यों ने इलाके में सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

इन घटनाओं ने मध्य पूर्व में चल रहे इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। एक तरफ इजरायल अपने सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान और हिज्बुल्लाह जैसे पक्ष इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखने के लिए सक्रिय हैं। इस टकराव का दायरा अब इतना व्यापक हो चुका है कि इसका असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग और वैश्विक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू इस संघर्ष से प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और शांति की अपील कर रहा है।

फिलहाल, हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और हर नया हमला स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना रहा है। आम नागरिकों के लिए यह समय सबसे कठिन है, क्योंकि वे इस संघर्ष के बीच फंसकर अपनी जान और सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या इस बढ़ते तनाव को कूटनीतिक प्रयासों के जरिए शांत किया जा सकेगा या फिर यह संघर्ष और अधिक गहराता जाएगा।

खाड़ी में टकराव का खतरा, खार्ग द्वीप पर कब्जे की धमकी से अमेरिका-ईरान संबंध और तनावपूर्ण

वॉशिंगटन/तेहरान। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब हालात और अधिक विस्फोटक होते नजर आ रहे हैं, जहां Donald Trump की नई चेतावनी ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। एक ओर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व ने खुले तौर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर संकेत दे दिया है कि कूटनीति और युद्ध की तैयारी एक साथ चल रही है। ताजा बयान में ट्रंप ने साफ कहा है कि यदि Iran जल्द ही युद्धविराम समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका उसके सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप, तेल के कुओं और बिजली संयंत्रों को पूरी तरह तबाह कर सकता है।

ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी किया, जिसमें उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब तक अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के कई अहम बुनियादी ढांचों को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें खत्म करने में देर नहीं की जाएगी। खार्ग द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से ईरान का अधिकांश कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजा जाता है। ऐसे में यदि इस द्वीप पर हमला या कब्जा होता है, तो न केवल ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।

ट्रंप की चेतावनी केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने साफ कहा कि यदि Strait of Hormuz को व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों,

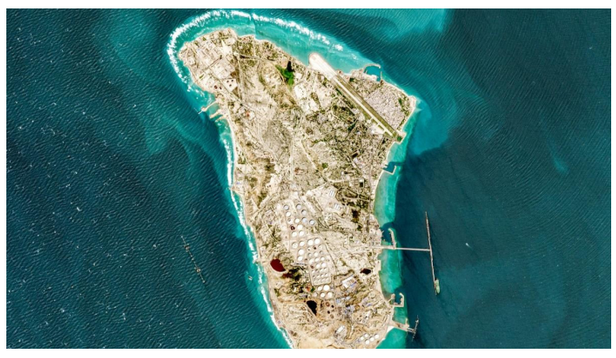

तेल के कुओं और यहां तक कि पानी आपूर्ति से जुड़े ढांचों को भी निशाना बना सकता है। यह बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है, ताकि उसे वार्ता की मेज पर झुकाया जा सके। हालांकि, इस सख्त रुख के बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना अभी भी बनी हुई है। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ समझौता जल्द संभव है और कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। उनके अनुसार, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 15 सूत्रीय योजना पर ईरान ने अधिकांश बिंदुओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान में नया नेतृत्व पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक और समझदार है, जिससे समझौते की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

लेकिन इन दावों के समानांतर जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। वॉशिंगटन लगातार खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार रख रहा है। यही कारण है कि ईरान की ओर से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की गई, तो वह फारसी खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा। यह कदम वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फारसी खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक हैं। यदि यहां तनाव बढ़ता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। Israel और अमेरिका दोनों ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी के कुछ देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुवैत में एक पानी और बिजली संयंत्र पर हमला किया गया, जिससे वहां स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। इसके अलावा ईरान ने इजरायल की एक तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, जो इस संघर्ष के विस्तार का संकेत देता है। ईरान की संसद और राजनीतिक नेतृत्व ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ वह युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। तेहरान ने इस बात से भी इनकार किया है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत चल रही है, जिससे यह साफ हो जाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि खार्ग द्वीप को लेकर दी गई यह चेतावनी केवल एक सैन्य धमकी नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दबाव का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है, और यदि इस पर चोट पहुंचाई जाती है, तो तेहरान को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। वहीं ईरान भी यह समझता है कि यदि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने जैसा कदम उठाया, तो यह वैश्विक स्तर पर बड़े संकट को जन्म दे सकता है। फिलहाल, स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीन पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल मध्य पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में ला खड़ा किया है, जहां हर देश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह तनाव बातचीत से सुलझेगा या फिर एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा।

संपादकीय

इंसानी जीपीएस का क्षरण

मनुष्य का मस्तिष्क प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। यह केवल सोचने और समझने का माध्यम ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के अनेक कार्यों का संचालक भी है। इनमें से एक महत्वपूर्ण क्षमता है—दिशा पहचानने और रास्ते याद रखने की। यह क्षमता हमें बिना किसी बाहरी सहायता के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से जीपीएस, के बढ़ते उपयोग ने इस प्राकृतिक क्षमता को धीरे-धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया है।

प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. एडवर्ड मोजर ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताई है। उनका मानना है कि जीपीएस पर अत्यधिक निर्भरता मानव मस्तिष्क की उस आंतरिक प्रणाली को प्रभावित कर रही है, जो हमें दिशा का बोध कराती है। पहले के समय में लोग अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और स्मृति के आधार पर रास्ते तय करते थे। वे रास्तों के मोड़, प्रमुख स्थलों और संकेतों को ध्यान में रखकर अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। यह प्रक्रिया न केवल उनकी दिशा-बोध क्षमता को मजबूत बनाती थी, बल्कि उनकी स्मरण शक्ति को भी विकसित करती थी।

आज के दौर में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोग किसी नए स्थान पर जाने से पहले उसके बारे में सोचने या समझने के बजाय सीधे अपने मोबाइल फोन में जीपीएस चालू कर लेते हैं। इसके बाद वे केवल स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। इस प्रक्रिया में उनका मस्तिष्क सक्रिय रूप से रास्ते को समझने या याद रखने का प्रयास नहीं करता। परिणामस्वरूप, वे एक ही रास्ते पर कई बार जाने के बाद भी उसे याद नहीं रख पाते। वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे मस्तिष्क में "ग्रिड सेल्स" नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे आंतरिक जीपीएस की तरह कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम किस स्थान पर हैं और हमें किस दिशा में जाना है। यही कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में एक मानसिक नक्शा तैयार करती हैं, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं। यह क्षमता जन्म के कुछ समय बाद ही विकसित हो जाती है और समय के साथ अनुभव के आधार पर मजबूत होती जाती है। जब हम लगातार जीपीएस का उपयोग करते हैं, तो इन ग्रिड सेल्स का उपयोग कम हो जाता है। जैसे किसी मांसपेशी का उपयोग न करने पर वह कमजोर हो जाती है, उसी प्रकार यह मानसिक क्षमता भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इसका प्रभाव केवल दिशा-बोध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इस स्थिति को समझने के लिए हम फोन नंबरों के उदाहरण को देख सकते हैं। पहले लोग अपने परिवार और मित्रों के कई फोन नंबर याद रखते थे। लेकिन आज के समय में हम सभी नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं और उन्हें याद रखने की आवश्यकता ही नहीं समझते। इससे हमारी स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, जीपीएस के अधिक उपयोग से हमारी दिशा पहचानने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। हालांकि तकनीक का उपयोग करना गलत नहीं है। जीपीएस ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है। यह हमें अनजान स्थानों पर आसानी से पहुंचने में मदद करता है और समय की बचत करता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम पूरी तरह इस पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करना बंद कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम तकनीक और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के बीच संतुलन बनाए रखें। हमें समय-समय पर बिना जीपीएस के भी यात्रा करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे-छोटे रास्तों को याद करने की कोशिश करनी चाहिए और आसपास के वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहेगा और हमारी दिशा-बोध क्षमता मजबूत बनी रहेगी। बच्चों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बचपन से ही उन्हें केवल तकनीक पर निर्भर रहने की आदत डाल दी जाएगी, तो उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें खेल-खेल में रास्ते पहचानने, नक्शे बनाने और दिशा समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वैज्ञानिक भी इस दिशा में लगातार शोध कर रहे हैं। वे यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क के इस प्राकृतिक जीपीएस सिस्टम को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे उपयोग किया जा सकता है। यदि इसमें सफलता मिलती है, तो मशीनें भी इंसानों की तरह वातावरण को समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो सकती हैं। अंततः, यह स्पष्ट है कि तकनीक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह हमारी प्राकृतिक क्षमताओं का विकल्प नहीं हो सकती। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति ने हमें जो क्षमताएं दी हैं, उनका संरक्षण और उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम केवल सुविधा के लिए उन क्षमताओं को नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे-धीरे हम उनसे वंचित हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम जीपीएस का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करें और अपने मस्तिष्क के कुदरती जीपीएस को भी सक्रिय बनाए रखें। यही संतुलन हमें तकनीकी युग में आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी मूल क्षमताओं को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।

दुश्मनों पर निगाह रहे और सभी से संवाद

"कूटनीतिक दायरे में पाकिस्तान की अचानक बढ़ी मौजूदगी भारत की स्थिति को लेकर असहज करने वाले सवाल खड़े करती है। ऐसे में हमें अपनी विदेश नीति, संबंधों और स्थिति पर आत्म-मंथन की जरूरत है। यह भी कि अदना सा देश युद्धरत अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करके भारत से आगे कैसे निकल गया व दुनिया उसकी सुन क्यों रही है?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बिल्कुल सही थे जब उन्होंने गत सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम एशिया संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि 'भारत कोई दलाल देश नहीं है'। जयशंकर, जो खुद एक पूर्व राजनयिक हैं और शब्दों का महत्व समझते हैं, उन्होंने हिंदी शब्द 'दलाल' का उपयोग किया, जिसका अर्थ है बिचौलिया, जब विपक्षी नेताओं ने उनसे ईरान के खिलाफ़ अमेरिका और इस्राइल के चल रहे चार हफ़्ते लंबे युद्ध को खत्म करवाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे पूछा।

समझा जा सकता है कि जयशंकर गुस्से में थे। माननीय सांसद स्पष्ट पूछ रहे थे – और, इस तरह - फ़ारस की खाड़ी में जारी संघर्ष में भारत की स्थिति की पाकिस्तान से तुलना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सैन्य-प्रतिष्ठान, जिसकी अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप के 'पसंदीदा फ़ील्ड मार्शल' आसिम मुनीर कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कर रहा है, जिसने ट्रंप को 6 अप्रैल तक युद्ध विराम की घोषणा करने में मदद की है। पाकिस्तान ने वार्ताओं की मेज़बानी करने की पेशकश की है; तुर्कीए और मिस्र अन्य संभावित स्थल हैं।

किसी भी ढंग से देखें, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान वैश्विक सुर्खियों में अपनी जगह बना पाया है। हो सकता है कि आगामी हफ्तों में इसका नतीजा न निकले। क्या पता, ट्रंप अभी भी ईरान पर ज़मीनी हमले का आदेश दे दें। लेकिन सर्वदलीय बैठक में मौजूद उन सांसदों ने, जिन्हें अन्यथा मुख्यतया केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर ज्यादा चिंता है, स्पष्टतया भांप लिया कि कुछ तो गंभीर गड़बड़ है; सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उनके घरों में प्रयोग होने वाले गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ गई हैं।

स्पष्टतः, जयशंकर को खफ़ा होने का हक है। पाकिस्तानी सैन्य-प्रतिष्ठान, जो दशकों

से निर्दोष भारतीयों पर एक के बाद एक भयानक हमलों का सूत्रधार रहा है, मुंबई से लेकर पहलगाम तक, जिन्होंने बार-बार लोगों की जान ली है, इन जघन्य अपराधों के लिए उसकी जवाबतलबी होनी चाहिए, न कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। शायद यह भारत के लिए आत्म-मंथन करने का उचित अवसर है कि हम -एक प्राचीन और अद्वितीय सभ्यता के लोग—इस आधुनिक और तेज़ रफ़्तार दुनिया में आखिर किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय लोग विदेश नीति के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते- इसी से संतुष्ट हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे विभिन्न प्रधानमंत्री हमें विदेशों के बड़े और बुरे प्रभावों से ज़्यादातर सुरक्षित रखते रहे हैं।

कुछ बातें हम जानते हैं। पहली, कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, भले ही प्रति व्यक्ति आय के मामले में (लगभग 2,700-3,000 डॉलर) हम देशों की सूची में 140वें स्थान पर हैं। दूसरी, भारतीय प्रवासियों का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका में। और तीसरी, विश्व मंच पर भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन है, न कि छोटा सा पाकिस्तान।

तब फिर, अदना सा पाकिस्तान, युद्धरत अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करके भारत से आगे क्यों निकल गया- इससे भी अहम यह कि दुनिया उसकी सुन क्यों रही है? चलिए, एक कदम पीछे हटें। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल यह नहीं कि क्या पाकिस्तान भारत से आगे निकलने में सफल रहा- वह खेल कई तरीकों से और कई मौकों पर खेला जा सकता है- बल्कि क्या भारत अपनी उस छवि पर टिक पाया है, एक ऐसा राष्ट्र, जिसके केंद्र में एक खास नैतिकता रही है; वह जिस पर हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही मजबूती से टिके रहे,जो कभी-कभार व्यावहारिक कारणों से थोड़ा भटक जाने की इजाज़त देता है (मसलन, जब नेतन्याहू गाज़ा पर बमबारी करते हैं या जब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं, तब चुप रहना), लेकिन फिर भी वह देश, जो किसी अनैतिक या अन्यायपूर्ण लड़ाई का समर्थन नहीं करता।

यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है-अपनी धुरी की ओर लौटने की ज़रूरत। इसलिए, भले मेज़बान बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अमेरिका संग मिलकर ईरान को तबाह करने के मंसूबे से हवाई हमले का आदेश देने से दो दिन पूर्व मोदी इस्राइल गए थे, लेकिन सच यह कि मोदी सरकार को उसके बाद अमेरिका-इस्राइल का खुलकर पक्ष लेने वाली अपनी पूर्व स्थिति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत ने शायद ट्रंप और नेतन्याहू की तरह ही सोचा था कि ईरान धरती के सबसे ताकतवर देशों का मुकाबला नहीं कर पाएगा।(भला किसकी हिम्मत है?) यह भी कि कि किसी भी सूरत में, अमेरिका-इस्राइल-यूएई त्रिकोण में उसके बहुत बड़े हित हैं- व्यापार, प्रवासी, रक्षा-और अपना शुरुआती रुख अपनाने से कुछ 'ब्राउनी पॉइंट्स' (अतिरिक्त लाभ) मिल सकेंगे।

बदकिस्मती से, वैसा हुआ नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध में एक पक्ष का साथ देकर,भारत ने उस 'मध्य मार्ग' को तज दिया, जिसकी सीख भारत के एक सपूत गौतम बुद्ध ने सदियों पहले दी थी। राजनीतिक रूप से दक्ष प्रधानमंत्री ने अवश्य उस व्यापक बेचैनी को भांप लिया होगा जो अमेरिकी मिसाइलों द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की निर्मम हत्या के बाद फैली थी;या ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हुई बमबारी पर, जिस पर अंततः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चर्चा जारी है। ऐसा नहीं कि भारतीय खामेनेई की कट्टर धार्मिकता या सोच के प्रशंसक थे;हमें रंज है कि कैसे एक-दो देश बेरोकटोक सारे नियम तोड़ रहे हैं। और इसलिए, भले ही भारत ने खामेनेई की हत्या की सीधे तौर पर निंदा करने से परहेज़ किया, परंतु विदेश सचिव विक्रम मिसरी को दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक-पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया। तत्पश्चात, मोदी और जयशंकर दोनों ने ही क्रमशः ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की-भले यह तेल से लदे भारत के जहाज़ों को 'फारस जलडमरूमध्य' से सुरक्षित गुज़रने में मदद करने के लिए ही क्यों न हो।

ईरान, जो भले ही लहूलुहान हुए पड़े हैं,पर झुके नहीं,इस खेल को और भी ज़्यादा सूझबूझ के साथ खेला है। वे जानते हैं कि भारतीय लोग -कश्मीर के आम लोग अपने ईरानी बंधुओं के लिए पैसे और गहने जमा कर रहे है, जबकि संभ्रांत वर्ग 'द ट्रिब्यून' जैसे अखबारों में अपने विचार लिख रहा है- सरकार के कदम से पूरी तरह सहज नहीं। कदाचित् अब कुछ ईरानी मिसाइलों पर 'थैंक्यू, इंडिया...' लिखा हुआ है। गत सप्ताह हमें विदेश नीति की कई सीखें मिली। पहली सीख यह कि सभी पक्षों से संवाद रखें, भले ही आप उनसे सहमत न भी हों- इसलिए, ईरान और इस्राइल दोनों से; और यूएई तथा सऊदी अरब से। दूसरी सीख, सभी पक्षों की बात सुनें-भारतीयों को एक कारण से इसलिए भी यह जानकर हैरत हुई कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की सफल कोशिश कर दिखाई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तक हमारी पहुंच अब नहीं रही; 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से सभी अखबार, टीवी चैनल और कई एक्स अकाउंट प्रतिबंधित कर दिए थे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, इस बारे में सिर्फ़ 'न्यूयॉर्क टाइम्स' और 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' से जान पाते हैं, और पाकिस्तान के 'डॉन' या 'द न्यूज़' से नहीं, तो आपकी जानने-समझने की क्षमता सीमित रह जाएगी।

तीसरी सीख यह कि आपको अपने पसंदीदा चाणक्य को नियमित पढ़ने से मिलती है 'जहां आपको अपने दोस्तों को करीब रखना चाहिए वहीं अपने दुश्मनों को और भी ज़्यादा करीब रखना चाहिए'।

प्रेरणा

अधिकार, ईमानदारी और आत्मसम्मान: एक रोटी की गहराई में छिपा जीवन का सत्य

मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह नैतिकता, आत्मसम्मान और सत्य जैसे गहरे मूल्यों पर आधारित है। रोटी, जो हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, वह भी केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्म, अधिकार और ईमानदारी का प्रतीक बन जाती है। जब हम "अधिकार की रोटी" की बात करते हैं, तो उसका अर्थ केवल यह नहीं होता कि हमने उसे कमाया है, बल्कि यह भी होता है कि हमने उसे किस प्रकार कमाया है।

एक राजा के मन में यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर "अधिकार की रोटी" क्या होती है। उसने अपने दरबार के विद्वानों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब एक विद्वान ब्राह्मण ने उसे सलाह दी कि वह नगर में रहने वाली एक वृद्ध महिला से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करे। यह बात अपने आप में ही महत्वपूर्ण थी कि एक साधारण-सी दिखने वाली महिला को इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने योग्य माना गया।

राजा उस महिला के पास पहुंचा और देखा कि वह एक साधारण झोपड़ी में बैठकर चरखे पर सूत कात रही थी। उसके पास न कोई वैभव था, न कोई दिखावा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने उससे पूछा, "माई, अधिकार की रोटी क्या होती है?" महिला ने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया कि उसकी रोटी का आधा हिस्सा अधिकार का है और आधा बिना अधिकार का। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने इसका कारण जानना चाहा।

महिला ने जो उत्तर दिया, वह केवल एक घटना का वर्णन नहीं था, बल्कि वह जीवन का एक गहरा दर्शन था। उसने बताया कि एक दिन वह अंधेरा होने के बाद भी सूत कात रही थी। तभी वहां से एक जुलूस गुजरा, जिसकी मशालों की रोशनी में उसने कुछ और समय तक सूत काता। उस सूत को बेचकर उसने आटा खरीदा और रोटी बनाई। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि जो सूत उसने दूसरों की रोशनी में काता, वह पूरी तरह उसका नहीं था। इसलिए उस रोटी का आधा हिस्सा ही उसका अधिकार है। यह कथा हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है कि अधिकार केवल उस पर होता है, जो पूरी तरह हमारे अपने परिश्रम और साधनों से प्राप्त हुआ हो। यदि उसमें किसी और की सहायता, संसाधन या योगदान शामिल है, तो हमें उसका उचित सम्मान और स्वीकार करना चाहिए। यह केवल ईमानदारी का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और नैतिकता का भी विषय है।

आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ गई है, लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता का असली मूल्य उसके पीछे छिपी ईमानदारी और परिश्रम में होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का हनन करके आगे बढ़ता है, तो उसकी सफलता भले ही बाहरी रूप से बड़ी लगे, लेकिन उसमें आत्मिक संतोष नहीं होता।

"अधिकार की रोटी" का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पारदर्शिता और सच्चाई को अपनाना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो हमें कभी यह डर नहीं रहेगा कि हमने कुछ गलत किया है। यही सच्चा आत्मविश्वास होता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह वृद्ध महिला अत्यंत साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसके विचार अत्यंत उच्च थे। यह दर्शाता है कि ज्ञान और नैतिकता का संबंध किसी की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्तर से नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही नैतिक और सच्चा हो सकता है, जितना कोई अमीर या शिक्षित व्यक्ति।

आज के डिजिटल युग में "अधिकार की रोटी" का महत्व और भी बढ़ गया है। हम अक्सर इंटरनेट से जानकारी लेते हैं, दूसरों के विचारों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा उनका उचित श्रेय देते हैं? क्या हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें किसी और का भी योगदान है? यदि नहीं, तो हम कहीं न कहीं "बिना अधिकार की रोटी" ही खा रहे हैं।

यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी लागू होता है। यदि समाज में लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होंगे, तो वहां न्याय, विश्वास और समृद्धि स्वतः स्थापित होगी। लेकिन यदि लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, तो समाज में असंतुलन और अशांति बढ़ेगी।

"अधिकार की रोटी" हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के योगदान का सम्मान करना चाहिए। यदि किसी ने हमारी मदद की है, तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सफलता में उसका भी हिस्सा है। यह भावना न केवल हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है।

इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चा सुख और संतोष केवल उसी चीज़ में होता है, जो हमने ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त की हो। भले ही वह कम हो, लेकिन उसमें जो आत्मिक शांति होती है, वह किसी भी बड़ी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान होती है। अंततः, "अधिकार की रोटी" केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम न केवल एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, बल्कि एक सच्चे और सम्मानित इंसान भी बन सकते हैं। इसलिए, जब भी हम अपने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल करें या कोई वस्तु प्राप्त करें, तो एक बार यह जरूर सोचें कि क्या यह वास्तव में हमारे अधिकार की है। यदि हां, तो उसे गर्व के साथ स्वीकार करें, और यदि नहीं, तो उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें।

तेल कम, गैस कम...आने वाले दिनों में क्या बिजली भी होगी कम? बढ़ती गर्मी के बीच लोगों के मन में नई टेंशन!

भीषण गर्मी ने अभी से ही लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में तापमान किस स्तर तक पहुंच सकता है। देश के कई हिस्सों में मार्च के अंतिम सप्ताह से ही तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोग अब खाना पकाने जैसे घरेलू कार्यों के लिए भी बिजली पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में जब अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी अपने चरम पर होगी, तब बिजली की मांग में भारी उछाल आना लगभग तय माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इस वर्ष भारत में अधिकतम बिजली मांग दो लाख पचास हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर होगा। पिछले वर्ष भी गर्मी के मौसम में मांग ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे और करीब दो लाख तीस हजार मेगावाट तक पहुंच गई थी। इस बार तापमान अधिक रहने की संभावना के चलते मांग और अधिक बढ़ सकती है।

हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व क्षेत्र दुनिया के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता माने जाते हैं। यहां जारी तनाव का सीधा असर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। हालांकि भारत अपनी बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयले से पूरा करता है, लेकिन गैस आधारित बिजली संयंत्र और आयातित ईंधन भी ऊर्जा संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर भारत की ऊर्जा लागत पर भी पड़ सकता है।

इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव के कारण लोग अब गैस की जगह बिजली आधारित उपकरणों का अधिक उपयोग करने लगे हैं। इंडक्शन चूल्हे, बिजली से चलने वाले हीटर और अन्य उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने कुल बिजली खपत को और बढ़ा दिया है।

हम आपको बता दें कि भारत की बिजली व्यवस्था अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है। कुल बिजली उत्पादन का लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा कोयला आधारित बिजली घरों से आता है। गर्मी के मौसम में जब मांग बढ़ती है, तब कोयले की खपत भी तेजी से बढ़ती है। कई बार यह स्थिति पैदा हो जाती है कि बिजली घरों के पास सीमित दिनों का ही कोयला भंडार बचता है।

कोयला खदानों से उत्पादन, रेलवे के जरिए परिवहन और बिजली घरों तक आपूर्ति की पूरी श्रृंखला पर दबाव बढ़ जाता है। यदि इस श्रृंखला में कहीं भी बाधा आती है तो इसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। यही कारण है कि हर साल गर्मी के मौसम में कोयले की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा बन जाती है।

देखा जाये तो बढ़ती मांग और ईंधन की लागत में संभावित वृद्धि के चलते बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि बिजली उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो वितरण कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार आम जनता पर बोझ कम रखने के लिए सब्सिडी और अन्य उपायों का सहारा ले सकती है, लेकिन लंबे समय तक यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं मानी जाती। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक ऊर्जा कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और घरेलू मांग लगातार बढ़ती है, तो भविष्य में बिजली दरों में संशोधन करना पड़ सकता है।

साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले महीनों में बिजली कटौती बढ़ेगी? यदि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अधिक बढ़ता है, तो कई राज्यों में बिजली कटौती की स्थिति बन सकती है। खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भी पीक समय के दौरान दबाव बढ़ सकता है। जब घरों, दफ्तरों और बाजारों में एक साथ बिजली की खपत बढ़ती है, तब ग्रिड पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यदि पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध नहीं होता, तो लोड प्रबंधन के तहत कटौती करनी पड़ सकती है।

उधर, केंद्र सरकार ने इस चुनौती को देखते हुए पहले से ही कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोयले के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने, बिजली घरों में न्यूनतम भंडार सुनिश्चित करने और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मांग प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, स्मार्ट ग्रिड तकनीक का उपयोग और उपभोक्ताओं को जागरूक करना इस दिशा में अहम कदम हो सकते हैं।

बहरहाल, स्पष्ट है कि वर्ष 2026 में भारत के सामने बिजली आपूर्ति को लेकर एक कठिन परीक्षा हो सकती है। भीषण गर्मी, वैश्विक ऊर्जा संकट, बढ़ती घरेलू खपत और कोयले पर निर्भरता जैसे कई कारक मिलकर इस चुनौती को और जटिल बना रहे हैं। ऐसे में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्ष मिलकर किस तरह इस स्थिति से निपटते हैं और आम लोगों तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

अभियान

पालीताणा: जहां पत्थरों में बसती है श्रद्धा, सीढ़ियों में तपस्या और वातावरण में अहिंसा का संगीत

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत जितनी विविधतापूर्ण है, उतनी ही गहरी और रहस्यमयी भी है। इसी विरासत का एक अद्वितीय और अनुपम उदाहरण है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताणा, जिसे 'मंदिरों का नगर' कहा जाता है। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि वह पवित्र धरा है जहां आस्था, कला, तप और अहिंसा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति केवल दर्शक नहीं रहता, बल्कि एक साधक बन जाता है, जो अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है।

शत्रुंजय नदी के किनारे और शत्रुंजय पर्वत की गोद में बसा पालीताणा एक ऐसा तीर्थ है, जिसकी पहचान केवल उसके भव्य मंदिरों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में बसती आध्यात्मिक ऊर्जा से होती है। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहां का हर पत्थर, हर सीढ़ी और हर मंदिर एक कहानी कहता है—भक्ति की, तपस्या की और मोक्ष की। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है, क्योंकि मान्यता है कि 24 तीर्थंकरों में से 23 ने इस पर्वत को अपनी उपस्थिति से पावन किया। विशेष रूप से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, का इस स्थान से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि उन्होंने यहां अनेक बार विचरण किया और उनके उपदेशों की गूंज आज भी इस पर्वत की वादियों में अनुभव की जा सकती है। यही कारण है कि पालीताणा को 'शाश्वत तीर्थ' कहा जाता है, जहां अनगिनत आत्माओं ने मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया। हर जैन श्रद्धालु का यह सपना होता है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार यहां आकर दर्शन करे और 3500 से अधिक सीढ़ियों की कठिन यात्रा पूरी करे।

शत्रुंजय पर्वत पर स्थित लगभग 900 मंदिर इस स्थान की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। इन मंदिरों में 17,000 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला इतनी सूक्ष्म और आकर्षक है कि देखने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह केवल स्थापत्य कला नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण की मूर्त अभिव्यक्ति है।

इन सभी मंदिरों में आदिश्वर मंदिर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर स्थित है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान आदिनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था। मंदिर में स्थापित उनकी स्वर्णमयी प्रतिमा और चारों ओर की बारीक नक्काशी भक्तों को एक दिव्य अनुभव कराती है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो आत्मा परमात्मा के और निकट आ गई हो।

पालीताणा की विशेषता केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यहां चौमुख मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर की संरचना चार दिशाओं में खुली हुई है, जिससे भगवान के दर्शन किसी भी दिशा से किए जा सकते हैं। यह मंदिर न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि धर्म और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती।

शत्रुंजय पर्वत पर मंदिरों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'टूंक' कहा जाता है। प्रत्येक टूंक का अपना अलग महत्व और इतिहास है। कुमारपाल टूंक और विमलशाह टूंक जैसे प्रमुख समूह इस स्थान की ऐतिहासिक गहराई को दर्शाते हैं। इन टूंकों में स्थित मंदिरों की नक्काशी और स्थापत्य कला यह प्रमाणित करती है कि उस समय के शिल्पकार कितने कुशल और समर्पित थे।

पालीताणा में केवल मुख्य मंदिर ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य पवित्र स्थल भी हैं, जो इसकी आध्यात्मिकता को और गहरा बनाते हैं। पुंडरीक स्वामी का मंदिर, अष्टपद मंदिर, रायण वृक्ष और भरत चक्रवर्ती से संबंधित स्थल—ये सभी स्थान इस पर्वत की पवित्रता को और बढ़ाते हैं। विशेष रूप से रायण वृक्ष के बारे में मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने इसके नीचे तपस्या की थी। इस वृक्ष के पास पहुंचकर श्रद्धालु एक विशेष शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं।

पालीताणा की यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या भी है। यहां की सीढ़ियां चढ़ते समय श्रद्धालु अक्सर मौन रहते हैं और खाली पेट यात्रा करते हैं। यह परंपरा केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मसंयम और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस कठिन यात्रा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ता है।

इस स्थान का एक और अनूठा नियम है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति पर्वत पर नहीं रुक सकता। मान्यता है कि रात के समय यहां देवताओं का वास होता है। यह नियम इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता को और भी विशेष बनाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति और आस्था के कुछ नियम ऐसे होते हैं, जिन्हें समझने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि विश्वास की आवश्यकता होती है।

पालीताणा की सबसे अनोखी पहचान यह भी है कि यह दुनिया का पहला कानूनी रूप से शाकाहारी शहर है। वर्ष 2014 में यहां मांसाहार, अंडे और पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यह निर्णय जैन धर्म के मूल सिद्धांत "अहिंसा परमो धर्मः" का सजीव उदाहरण है। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है, जो यह सिखाती है कि सभी जीवों के प्रति करुणा और दया रखना ही सच्चा धर्म है।

आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में पालीताणा जैसे स्थान हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने भीतर झांकने, अपने अस्तित्व को समझने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। यहां की शांति, यहां की ऊर्जा और यहां का वातावरण हमें यह अनुभव कराता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है।

पालीताणा केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत संदेश है—भक्ति का, अहिंसा का और आत्मज्ञान का। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सादगी, सत्य और करुणा को अपनाएं, तो हम भी अपने भीतर उसी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं, जो इस पवित्र पर्वत की हर शिला में बसती है। यही कारण है कि जो भी यहां एक बार आता है, वह केवल दर्शक बनकर नहीं लौटता, बल्कि अपने साथ एक नया दृष्टिकोण, एक नई शांति और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च को गुजरात की यात्रा पर, वाव-थराद में 19,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

▶▶ भारत सरकार के ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा रेलवे मंत्रालय के 10,900 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा

▶▶ गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग अंतर्गत 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जाएगा

▶▶ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रधानमंत्री गुजरात के 34 जिलों में 38,949 आवासों में नागरिकों का गृह प्रवेश कराएंगे

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च, 2026 को गुजरात की यात्रा पर आएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाव-थराद से भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के कुल मिलाकर 19,806.9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें भारत सरकार के ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा रेलवे मंत्रालयों के 10,921 करोड़ रुपए के तथा गुजरात सरकार के शहरी विकास, जल संसाधन, जलापूर्ति, सड़क एवं भवन, जीआईडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन तथा आदिजाति विकास विभागों के 8,886 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास शामिल है। वाव-थराद में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सहित भारत एवं गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत गुजरात में 10,921 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तथा शिलान्यास

उल्लेखनीय है कि कच्छ जिले के खावडा में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पार्क निर्माणाधीन है। आगामी 31 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी खावडा के आरई पार्क के लिए ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 3,645 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स द्वारा हजारों मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का राष्ट्रीय ग्रिड के साथ प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके कारण हरित ऊर्जा की व्यापकता तथा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बनेगी।

इसके अलावा; भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अंतर्गत इडर-बारडोली बाईपास फोर लेन रोड (705 करोड़ रुपए की लागत से) और धोळावीरा-मौवाणा-वोवा-सांतलपुर सेक्शन (575 करोड़ रुपए की लागत से) शिलान्यास तथा अहमदाबाद-धोलेरा पैकेज 1 (1,298 करोड़ रुपए की लागत से), पैकेज 2 (1,415 करोड़ रुपए की लागत से, पैकेज 3 (1,034 करोड़ रुपए की लागत से और पैकेज 4 (1,358 करोड़ रुपए की लागत से) का लोकार्पण किया जाएगा। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के 891 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें हिंमतनगर-खेडब्रह्मा ब्रॉडगेज लाइन, गांधीधाम-आदिपुर के बीच क्वाड्रपलिंग तथा राजकोट-कालानुस डबलिंग प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कालानुस-जामनगर डबलिंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी प्रकार; खेडब्रह्मा-हिंतमनगर-असारवा ट्रेन को खेडब्रह्मा से हरी झंडी दिखाई जाएगी। कुल मिलाकर भारत सरकार के इन तीन मंत्रालयों के 10,921 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा।

गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग अंतर्गत सर्वाधिक 5,295.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास

आगामी 31 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 8,886 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास विभागांतर्गत सर्वाधिक 5,295.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास किया जाने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स में मुख्य रूप से अहमदाबाद एवं गांधीनगर के विकास कार्य शामिल हैं; जिनमें अहमदाबाद में खारीकट कैनाल विकास, अहमदाबाद महानगर पालिका की बीआरटीएस व एएमटीएस बस सर्विस का मॉडर्नाइजेशन, वर्तमान सुभाषब्रिज को तोड़कर नए फोर लेन ब्रिज का कन्स्ट्रक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आवासीय घरों का निर्माण, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम आदि जैसे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास शामिल हैं।

गांधीनगर में ईडब्लूएस के लिए आवासीयों घरों का निर्माण, गांधीनगर महानगर पालिका के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से अडालज टीएसपीएस तक खुले खुदाई कार्य (लंबाई : 2420 मीटर) और माइक्रोटनलिंग (लंबाई : 3180 मीटर) द्वारा 1800 मिमीलीटर गटर ट्रंक डालने, पेथापुर में 15 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, रांधेजा में 4 तालाबों की इंटरलिंकिंग तथा स्टॉर्म वॉटर लाइन बिछाने का कार्य आदि प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास किया जाएगा।

शहरी विकास विभाग के अलावा; गुजरात सरकार के जल संसाधन, जलापूर्ति, सड़क एवं भवन, जीआईडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, आदिजाति तथा ग्रामीण विकास विभागों के भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत गुजरात के 34 जिलों के 38,949 आवासों में नागरिकों का गृह प्रवेश कराएंगे, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए अपने घर का सपना साकार होगा।

वडोदरा - नागदा सेक्शन पर 'कवच 4.0' का सफलतापूर्वक कमीशन, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने कवच प्रणाली से सज्ज स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

मुंबई - नई दिल्ली मुख्य मार्ग का अधिकतम रुट अब कवच प्रणाली से सज्ज पश्चिम रेलवे द्वारा रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करने के क्रम में 30 मार्च, 2026 को वडोदरा - नागदा सेक्शन पर कवच 4.0 सिस्टम को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा वडोदरा स्टेशन से कवच से सज्ज स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गयी। इस प्रकार मिशन रफ़्तार के अंतर्गत मुंबई - नई दिल्ली मुख्य मार्ग के पश्चिम रेलवे के निर्धारित 693 रुट किलोमीटर में से 559.5 रुट किलोमीटर पर यानी अधिकतम रुट पर इस प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने इस अवसर पर बताया कि वडोदरा - नागदा सेक्शन के अंतर्गत वडोदरा से मंगल महुडी सेक्शन (122.5 Rkm) और पंचपिपलिया - नागदा (102.01 Rkm) सेक्शन के बीच में यानी कुल 224.51रुट किलोमीटर पर कवच प्रणाली को आज सफलतापूर्वक लांच किया गया है। मंगल महुडी से पंचपिपलिया के बीच इस प्रणाली को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसे आटोमेटिक सिगनलिंग के साथ पूरा कर लिया जायेगा। रेलवे द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2025 -26 में कुल 659.5 रुट किलोमीटर पर कवच प्रणाली स्थापित की गयी है। वडोदरा मंडल द्वारा इससे पहले जनवरी 2026 में वडोदरा - विरार सेक्शन पर कवच सिस्टम चालू किया गया था और आज वडोदरा से गोधरा होते हुए नागदा तक इसे कमीशन किया गया है। कवच एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और यह मानवीय गलतियों के जोखिम को कम करने के लिए ट्रेन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। जो कि मानवीय त्रुटि के कारण 'सिग्नल पासिंग एट डेंजर' (SPAD) से होने वाले परिणामों को रोकती है।

वडोदरा–नागदा सेक्शन पर इस जटिल कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्येक स्टेशन तथा प्रत्येक एब्सोल्यूट/ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सेक्शन के लिए पृथक योजना तैयार की गई, पटरियों पर 6000 से अधिक स्थानों पर RFID टैग का प्रोग्रामिंग एवं स्थापना कार्य किया गया, 26 स्टेशनों, 13 मध्य-खंडों तथा लोकोमोटिव के बीच सतत रेडियो संचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, प्रत्येक स्टेशन पर कुल 39 रेडियो संचार टावर एवं आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए, पूरे मार्ग पर UP एवं DN दोनों दिशाओं में लगभग 600 किमी लंबाई की OFC केबल बिछाई गई, साथ ही प्रत्येक स्टेशन, मध्य-खंड एवं LC गेट पर आधुनिक 'कवच' उपकरण स्थापित कर उन्हें मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली से एकीकृत किया गया, लोकोमोटिव में भी 'कवच' उपकरण लगाए गए तथा अंततः संपूर्ण प्रणाली का सफलतापूर्वक ट्रायल एवं परीक्षण किया गया।

'कवच' प्रणाली अपने यूरोपीय समकक्षों (ETCS) की तुलना में बहुत सस्ती है। अभी तक WAP-7, WAG9, WAP5 लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगाई गयी है। जल्द ही, इसे दूसरे लोकोमोटिव पर भी शुरू किया जाएगा। अब तक पश्चिम रेलवे पर कुल 364 लोकोमोटिव में 'कवच' प्रणाली लगाई जा चुकी है।

पश्चिम रेलवे आधुनिक एवं स्वदेशी तकनीकों को अपनाकर सुरक्षित, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख रेल नेटवर्क के निर्माण हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

सूरत में महाकाल ग्रुप के खिलाफ गंभीर आरोप: भूमि घोटाला, वकील-पुलिस सांठगांठ पर चर्चा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात का मिनी इंडिया कहे जाने वाला सूरत, विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ हर प्रांत से लोग आकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में बसने लगे, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई, ज़मीन की कीमतें बढ़ने लगीं और इसका फायदा उठाते हुए कुछ बड़े बिल्डर महाकाल ग्रुप के उन वकीलों के ज़रिए करोड़ों रुपये की ज़मीनें बिकवा रहे हैं जो अदालतों में वकालत नहीं करते। आज भी, बुज़ुर्ग वकील गुज़ारा करने के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर वकालत करने को मजबूर हैं। जीवन भर वकालत करने के बावजूद वे मुश्किल से एक घर, एक छोटा दफ्तर या एक चारपहिया वाहन ही खरीद पाए हैं। दूसरी ओर, कुछ वकील सर्टिफिकेट लेने के बाद भी अदालत में कभी पेश नहीं हुए, लेकिन वे अपने वकील के ज़रिए तभी केस दर्ज कराते हैं जब जजों की बेंच किसी जज के साथ आती है। इस तरह, ऐसे वकील घर बनवाकर आलीशान दफ्तर, महंगी गाड़ियाँ और बंगले बना लेते हैं। ये वकील अपने दफ्तरों में बैठकर बड़े-बड़े केस निपटाते हैं। इनके दफ्तरों में तथाकथित अहंकारी और कुख्यात असामाजिक तत्व पनाह लेते हैं। कृषि व्यवसाय में लगे बड़े किसानों के खिलाफ अत्याचार और अन्य मामलों में ऐसे वकील पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें जेल भेज चुके हैं। शहर के बड़े बिल्डर

सुबह-शाम ऐसे वकीलों को अपने यहाँ बुलाते हैं। किसानों के साथ जमीन के मामलों में उन्हें असामाजिक तत्वों या पुलिस से फोन आते हैं और उन्हें धमकाया जाता है। सालों से वकालत कर रहे वकीलों के पास आलीशान दफ्तर नहीं होते। वहीं, ऐसे उपद्रवी वकील जो अदालतों में वकालत नहीं करते, उनके पास आलीशान दफ्तर होते हैं। और बिना वकालत किए ये वकील मौज-मस्ती करते हैं। उनके बड़े-बड़े फार्महाउसों में बड़ी-बड़ी पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में बड़े-बड़े आईपीएस और आईएएस अधिकारी मौजूद रहते हैं। नेताओं के आशीर्वाद से शहर में महाकाल ग्रुप नाम का एक गिरोह बना है जो राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती तय करता है। इस गिरोह के ज्यादातर सदस्य कट्टरपंथी हैं। इस गिरोह के सदस्य आयकर विभाग के छापे मारते हैं, जिनके बिल्डरों या उद्योगपतियों के यहाँ या तो छापेमारी होती है या उन्हें वहाँ बसाया जाता है। उनके अधीन राजस्व विभाग के अधिकारियों का

तबादला नेताओं के आशीर्वाद से सूरत शहर में कर दिया जाता है। करोड़ों रुपये की जमीनें ऐसे वकीलों द्वारा कीमत तय करके, कट्टरपंथियों की मदद से और धमकाकर हड़प ली जाती हैं। फिलहाल, महाकाल समूह के चार हाथ मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों पर हैं। यह स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सूरत के राजुगीजू अल्थान गांव के एक बड़े किसान के खिलाफ उनकी 73AA जमीन को लेकर अत्याचार का मामला दर्ज किया गया और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के कारण बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अगर बड़े किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सूरत जिले के तथाकथित छोटे किसानों के फार्महाउस वास्तव में असामाजिक तत्वों के कब्जे में हैं। और वहीं से बिल्डरों को संरक्षण मिलता है। कपड़ा और हीरा उद्योग में गबन करने वालों को उनके गिरोह द्वारा संरक्षण दिया जाता है। बिल्डर भी उन्हें संरक्षण देते हैं ताकि उन्हें बाजार से लिया गया पैसा वापस न करना पड़े। पुलिस से बचाने के लिए उन्हें फार्महाउसों में पनाह दी जाती है। और पुलिस भी इसमें शामिल है। तत्कालीन अधिकारियों ने अत्याचार के मामलों की आड़ में राजुगीजू से करोड़ों रुपये लूटे। महाकाल समूह का एक सिंडिकेट बनाया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, असामाजिक तत्वों, वकीलों और लाइसेंसधारियों सहित 25 से 30 लोगों का समूह था। ये वकील खुद वकालत नहीं करते और तय करते हैं कि किस मामले को किस न्यायाधीश की पीठ में ले जाना है। और अगर उनके वकील भरोसेमंद हैं और जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिस भी न्यायाधीश की पीठ में मामला जाता है, उसमें जीत जाते हैं, तो ऐसे वकील बिना किसी तरह की वकालत किए करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इसलिए, अगर ऐसे वकील वास्तव में वकालत नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाम बार काउंसिल से हटा दिए जाने चाहिए। वे एसी दफ्तरों में बैठकर अपने पक्ष में मामले लड़ रहे हैं। और ये लोग केस जीतने का वादा करके पैसे ले रहे हैं। ऐसे वकीलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही, उनके दफ्तरों की मेजों पर पड़ी बेकार फाइलों की भी जांच होनी चाहिए। महाकाल समूह के सदस्यों की छोटी से छोटी जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब कुछ पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारी तबादलों के बाद आते हैं, तो महाकाल समूह उनके परिवार के आने तक उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराता है। महाकाल समूह में भी काम का बंटवारा अलग-अलग सदस्यों के बीच है, जिनमें से कुछ कर्मचारी/अधिकारियों के तबादलों में शामिल हैं।

असारवा – खेड़ब्रह्मा के बीच 01 अप्रैल से नई मेमू ट्रेन सेवा का नियमित संचालन

यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिनांक 31 मार्च 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ब्रह्मा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद (असारवा) के बीच नई रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे।

v प्रारंभिक ट्रेन सेवा (Inaugural Run)

दिनांक 31 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 09439 खेड़ब्रह्मा–असारवा मेमू (one way) खेड़ब्रह्मा से 16:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा 19:45 बजे असारवा पहुचेंगी।

v नियमित ट्रेन सेवा

ट्रेन संख्या 69251 असारवा–खेड़ब्रह्मा मेमू दिनांक 01 अप्रैल 2026 (बुधवार) से सप्ताह के सभी दिनों में असारवा से सायं 18:25 बजे प्रस्थान कर 21:10 बजे खेड़ब्रह्मा पहुँचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 69252 खेड़ब्रह्मा–असारवा मेमू दिनांक 02 अप्रैल 2026 (गुरुवार) से सप्ताह के सभी दिनों में खेड़ब्रह्मा से प्रातः 06:45 बजे प्रस्थान कर 09:30 बजे असारवा पहुँचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन सरदारग्राम, नरोडा, डभोड़ा, नांदोल दहेगाम, रखियाल, तालोद, प्रांतिज, सोनासन, हिम्मतनगर एवं इडर रेलवे स्टेशनों पर ठहरेगी।

यह ट्रेन 08 कोच की मेमू रेक के साथ संचालित की जाएगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा गंगाधरा में प्रथम ग्रीनफील्ड,गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ,मुंबई मंडल ने रिकॉर्ड 8 माह में किया निर्माण; सूरत के औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बढ़ावा

पश्चिम रेलवे ने 30 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल मंडल के अंतर्गत गंगाधरा में रेलवे भूमि पर अपने पहले ग्रीनफील्ड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस टर्मिनल का उद्घाटन पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने इस अवसर पर पहली कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर परिचालन का शुभारंभ भी किया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस टर्मिनल का विकास मेसर्स प्रिस्टीन कनेरिया लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसे मात्र 8 महीनों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, जो भारतीय रेल पर अब तक का सबसे तेजी से निर्मित गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है।

यह अत्याधुनिक टर्मिनल लगभग 44,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला पूर्णतः रेलवे भूमि पर विकसित किया गया है और सूरत के औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यह टर्मिनल स्टील, वस्त्र, सीमेंट, फ्लाई ऐश, रसायन तथा उर्वरक सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रबंधन में सक्षम होगा, जिससे माल लदान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा ग्राहकों को कुशल और प्रभावी लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्राप्त होंगी। इस टर्मिनल के शुरू होने से पश्चिम रेलवे के माल परिवहन क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सड़क से रेल की ओर निर्बाध परिवहन को प्रोत्साहित करते हुए यह टर्मिनल सड़क यातायात में कमी लाएगा, कार्बन उत्सर्जन घटाएगा तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। साथ ही, मालगाड़ियों के तेज आवागमन और त्वरित टर्नअराउंड से परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे माल एवं यात्री दोनों सेवाओं के लिए एक सुदृढ़ और उच्च गति वाले रेल नेटवर्क के विकास को बल मिलेगा।

यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे की अवसंरचना विकास, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं तथा भारत सरकार के गति शक्ति विजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे इस प्रकार की पहलों के माध्यम से सतत, कुशल एवं भविष्य के अनुरूप परिवहन समाधान प्रदान करते हुए देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी।

पश्चिम बंगाल में चुनाव पूर्व मतदाता सूची विवाद: लाखों नाम हटाए गए, न्यायाधिकरण का गठन अभी तक नहीं हुआ

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पश्चिम बंगाल में चुनाव बस कुछ ही दिनों के भीतर होने वाले हैं, और मतदाता सूची को लेकर हर दिन नए गुट उभर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में यह दावा किया गया था कि मतदाता सूची सुधार के बाद प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन शंकाएं दूर होने के बजाय स्थिति और भी जटिल हो गई है।

पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, बीएलओ, डॉक्टरों, वकीलों और पुलिसकर्मियों के नाम मतदाता सूची से गायब होने की खबरें आ रही हैं। ये वे लोग हैं जिनके नाम विचाराधीन थे। हालांकि विवाद के बाद पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम हटाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है, क्या अन्य मामलों में भी यही स्थिति है? क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें न्यायाधिकरण में सुनवाई मिल रही है? यदि न्यायाधिकरण का गठन अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या लाखों लोग मतदाता सूची और मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रह जाएंगे? राज्य में विचाराधीन मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने के कारण ये सवाल उठ रहे हैं

। राज्य में कुल 60 लाख से अधिक मामलों की जांच चल रही है। 705 न्यायिक अधिकारियों की एक टीम अब तक 37 लाख मामलों का फैसला कर चुकी है। दो पूरक सूचियां जारी की जा चुकी हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अब तक कितने नाम हटाए गए हैं।

लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य भर में 15 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। राज्य में सबसे अधिक मामले मुर्शिदाबाद में 11 लाख और मालदा में 8.28 लाख दर्ज किए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में डॉक्टरों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों, बीएसएफ कर्मियों, प्रोफेसरों और आम किसानों और मजदूरों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

प्रभावित लोगों का दावा है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। लेकिन सबूत पेश करने के बावजूद उनके नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए हैं। खबरों के मुताबिक, फार्मासिस्ट खैरुल आलम कहते हैं, "मेरे दो भाई और एक बहन डॉक्टर हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक इंटर्नशिप कर रहे हैं।" हमने अपने डॉक्टर पंजीकरण प्रमाण पत्र, माध्यमिक प्रवेश पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और 2002 के पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा किए थे। फिर भी, दोनों डॉक्टरों के नाम हटा दिए गए। उनकी बहन, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ खालिदा खातून कहती हैं, "मैंने सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। अब मैं मतदाता नहीं हूं। कोई कारण नहीं बताया गया है। मैं इसे न्यायाधिकरण में चुनौती दूंगी।" हमारे नाम अब क्यों हटाए गए हैं जबकि हमारे दादा और परदादा 1952 की मतदाता सूची में थे?

इन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब न्यायाधिकरण के गठन के बाद ही मिलेंगे। यहाँ अभी तक न्यायाधिकरण का गठन नहीं हुआ है। फिर वे अपील कैसे करेंगे? "ये है नया भारत का सम्पा"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअल उपस्थिति में तापी जिले को मिली 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भेंट

▶▶ तापी के उच्छल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तापी के 136 गाँवों के लिए 962 करोड़ रुपए की उद्वहन सिंचाई योजना का ई-लोकार्पण किया, 28 हजार हेक्टेयर भूमि को होगा लाभ

▶▶ 651 करोड़ रुपए की बोरीसावर योजना के ई-शिलान्यास से सोनगढ-व्यारा के 29 गाँवों की 8 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा से लाभान्वित होगी

▶▶ केबिनेट मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल तथा राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित उपस्थित रहे

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों तथा तापी जिले के विकास के लिए अनुमानित 1600 करोड़ रुपए की उकाई जलाशय आधारित सोनगढ, उच्छल, नीझर उद्वहन सिंचाई योजना तथा बोरीसावर योजना का ई-लोकार्पण व ई-शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सेचुरेशन एप्रोच पर बल दिया है। प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान वनबंधु कल्याण योजना के जरिये आदिजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कनेक्टिविटी के लिए भी परिणामोन्मुखी कार्य किए हैं।

श्री पटेल ने जोड़ा कि पानी विकास का मुख्य आधार है। आज इंजीनियरिंग कौशल से हम उकाई बांध का पानी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचा रहे हैं। सोनगढ, उच्छल तथा नीझर उद्वहन सिंचाई योजना और बोरीसावर उद्वहन सिंचाई योजना से हजारों किसानों को बारहों महीने पानी मिलेगा तथा उनकी खेती समृद्ध होगी।

उच्छल तहसील के बाबरघाट में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के आदिजाति विकास मंत्री तथा तापी जिला प्रभारी श्री नरेशभाई पटेल ने कहा कि तापी मैया दक्षिण गुजरात के लिए जीवनदायिनी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उकेरे गए विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने जोड़ा कि जन कल्याण तथा ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण द्वारा राज्य सरकार सुदूरवर्ती नागरिकों तक सुख-सुविधाएँ पहुँचाने को कटिबद्ध है।

उन्होंने किसानों को दोनों उद्वहन सिंचाई योजनाओं का लाभ लेने के साथ ड्रिप इरीगेशन पर मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर जल संसाधन तथा जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने गुजरात के सुचारु जल प्रबंधन का विवरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से लोकार्पित 962.12 करोड़ रुपए की उकाई जलाशय योजना आधारित सोनगढ, उच्छ, नीझर उद्वहन सिंचाई योजना से सोनगढ, उच्छल, नीझर तथा कुकरमुंडा के 136 गाँवों की 28 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही; 651.37 करोड़ रुपए की लागत से साकार हो रही बोरीसावर योजना द्वारा सोनगढ एवं व्यारा तहसीलों के 29 गाँवों की 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी सिंचाई सुविधा से सज्ज होगी।

खेल, उद्योग तथा पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित ने भी आदिवासी क्षेत्र तथा आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के कामकाज की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने दो उद्घाटित बहुमूल्य योजनाओं तथा किसानों की समृद्धि की झाँकी दर्शाने वाली लघु फिल्म देखी।

इस अवसर पर उच्छल तहसील के बाबरघाट में मंत्रियों सर्वश्री नरेशभाई पटेल, ईश्वरसिंह पटेल तथा जयरामभाई गामित ने कार्यक्रम स्थल पर तापी मैया के नीर का स्वागत-सत्कार किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जालमसिंह वसावा, जिले के अग्रणी श्री सूरजभाई वसावा, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री पी. सी. व्यास, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन गर्ग, विधायक श्री मोहनभाई कोंकणी सहित उच्चाधिकारी, पदाधिकारी, अग्रणी, आमंत्रित, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन-किसान उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं को गति देने का महत्वपूर्ण निर्णय

वनबंधु कल्याण योजना के तहत आदिवासी गांवों के स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्यों और स्ट्रक्चर निर्माण के लिए 362 करोड़ रुपए के कार्यों को दी मंजूरी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के अंबाजी से लेकर उमरगाम तक के समग्र आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए गांवों तक आधारभूत सुविधाओं को और भी सुलभ बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में आदिवासी क्षेत्रों के गांवों के स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए 325.81 किमी लंबाई के कार्यों तथा स्ट्रक्चर निर्माण के कार्यों सहित 293 कार्यों के लिए कुल 362.57 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत आदिवासी समुदायों तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं आसानी से और समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को मंजूर किया है।

आदिवासी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण होने से विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचने में आसानी होगी।

इतना ही नहीं, आकस्मिक परिस्थिति में मरीजों को निकट स्थित स्वास्थ्य केंद्र तक तेजी से पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की इस पहल से आदिवासी क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलने से 'सबका साथ, सबका विकास' का ध्येय भी साकार होगा।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

केटरिंग यूनिटों के आवंटन के लिये ई–नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक –रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे ने मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर केटरिंग यूनिटों के आवंटन के लिये ई–नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को **IREPS** वेबसाईट (ई–ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है। केटलॉग संख्या : CTG-RTM-DIV-26. अनुबंध का प्रकार : Catering Units. लॉट नं : Catg-RTM-THDR-GMU-9-23-1, Catg-RTM-PPD-GMU-12-23-1, Catg-RTM-RAU-GMU-8-23-1, Catg-RTM-PIP-GMU-256-26-1, Catg-RTM-RJQ-GMU-7-23-1, Catg-RTM-FTD-GMU-24-23-1, Catg-RTM-FTD-GMU-25-23-1, Catg-RTM-DWX-SMU-251-26-1, Catg-RTM-RNJ-SMU-34-24-1, Catg-RTM-MGN-SMU-252-26-1, Catg-RTM-THDR-SMU-253-26-1, Catg-RTM-NBH-SMU-255-26-1. अनुबंध की अवधि – 5 वर्ष ई–नीलामी की तिथि और समय सभी लॉट के लिये ई–नीलामी दिनांक 14/04/2026 को 11:30 बजे प्रारंभ होगी। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। **IREPS** के ई–ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटसाईज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-525

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

सत्यमेव जयते
ગુજરાત સરકાર

विकसित भारत विकसित गुजरात

GUJARAT URBAN DEVELOPMENT YEAR 2025
20 वर्ष शहरी विकास

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
के कर-कमलों द्वारा

₹19,800 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का
लोकार्पण एवं शिलान्यास

विशेष अतिथि
श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

गरिमामय उपस्थिति

श्री हर्ष संघवी
माननीय उप मुख्यमंत्री, गुजरात

श्री शंकरभाई चौधरी
माननीय अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा

केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाएँ

- शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग की 44 परियोजनाएँ
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 6 परियोजनाएँ
- विद्युत मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय की 3-3 परियोजनाएँ
- जल संसाधन विभाग की 5 परियोजनाएँ
- गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) की 3 परियोजनाएँ
- स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सड़क एवं भवन विभाग की 2-2 परियोजनाएँ
- जलापूर्ति एवं जनजातीय विकास विभाग की विविध परियोजनाएँ

दिनांक: 31 मार्च 2026 | समय: सायं 04:00 बजे | स्थान: नाणी, वाव-थराद

विकास की ऐतिहासिक सौगातें

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं में विस्तार
1600 से अधिक मरीजों के परिजनों के लिए रियायती दरों पर आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था

रेल कनेक्टिविटी का विस्तार
₹891 करोड़ की लागत की रेल परियोजनाओं से 94 किमी. तक रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी जिससे यात्रा सुगम होगी व अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी।

अहमदाबाद-धोलेरा SIR मार्ग को मिलेगी ऐतिहासिक गति
₹5,105 करोड़ की लागत से बनने वाले 109 किमी एक्सप्रेस-वे से यात्रा का समय लगभग 2 घंटे 15 मिनट से घटकर मात्र 45 मिनट रह जाएगा। यह व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।

विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति
₹3645 करोड़ की लागत से 6000 MVA + 4.5 GW क्षमता वाली 958 सर्किट किमी.(CKM) से अधिक ट्रान्समिशन लाइन नेटवर्क के विस्तार से 30 लाख से अधिक आवासों को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति

ट्रैफिक समस्या में राहत
अडालज के 1.02 किमी लंबे ओवरब्रिज से अन्नपूर्णा सर्कल पर अब ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी। हजारों नागरिकों की दैनिक यात्रा अधिक सुगम, सरल और सुरक्षित होगी

जनजातीय युवाओं को शिक्षा के नए अवसर
628 छात्रों के समावेश वाले छात्रावास में सुरक्षित आवास, अध्ययन और भोजन जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।

पर्यटन अनुभव बनेगा और बेहतर
₹68 करोड़ की पर्यटन परियोजनाओं से पर्यटकों के लिए हेरिटेज साइट्स का अनुभव होगा और भी रोचक व आनंददायक, स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिकता का स्पर्श मिलेगा।

ग्रामीण परिवारों को अपना पक्का घर
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 34 जिलों में 38,949 नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश। इससे हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा।

जल सुविधा में विस्तार
110 किमी लंबी पाइप लाइनों का निर्माण, 128 गांवों के 280 तालाब नर्मदा के जल से जुड़ेंगे, जिससे गुजरात के 92,000 एकड़ खेती की ज़मीनों को मिलेगा सिंचाई का व्यापक लाभ

औद्योगिक विकास को मजबूत आधार
साणंद II और नरोडा GIDC से 2,416 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1,150 से अधिक उद्योगों को विविध इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, सड़क और परिवहन सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज चैनल पर DD NEWS